भारत सरकार

खान मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 3809

दिनांक 18.12.2024 को उत्तर देने के लिए

खनिज अन्वेषण को बढ़ावा देना

3809 श्री विजय बघेल:

क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :
(क) सरकार द्वारा भारत में खनिज अन्वेषण को बढ़ाने के लिए कार्यान्वित की गई प्रमुख पहलों, विशेष रूप से राष्ट्रीय भूवैज्ञानिक डेटा रिपोजिटरी (एनजीडीआर) पोर्टल के माध्यम से तथा अन्वेषण व्यय को पूरा करने के लिए नई प्रतिपूर्ति योजनाओं का ब्यौरा क्या है; और
(ख) खनिज अन्वेषण को बढ़ावा देने तथा खनन क्षेत्र में स्टार्ट-अप्स और सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) के बीच नवाचार को प्रोत्साहित करने में राष्ट्रीय खनिज अन्वेषण ट्रस्ट (एनएमईटी) की भूमिका क्या है?

उत्तर

कोयला और खान मंत्री
(श्री जी. किशन रेड्डी)

(क) : राष्ट्रीय भूविज्ञान डेटा कोष (एनजीडीआर) पोर्टल एक क्लाउड-आधारित पोर्टल है जिसे सभी बेसलाइन और गवेषण-संबंधित भू-वैज्ञानिक डेटा को एकल जीआईएस प्लेटफॉर्म पर डालकर देश के खनिज गवेषण कवरेज को तीव्र करने और सुविधाजनक बनाने, सभी हितधारकों के लिए इसे उपलब्ध कराने और एकल विंडो प्रणाली में भू-स्थानिक डेटा का प्रसार करने के लिए बनाया गया है। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (जीएसआई) एनजीडीआर पोर्टल का नोडल एजेंसी है और इसे राष्ट्रीय खनिज खोज न्यास (एनएमईटी) द्वारा वित्त पोषित किया जाता है। वर्तमान में, जीएसआई की 9171 रिपोर्टें, हितधारकों की 395 रिपोर्टें और 35 से अधिक परतों से संबंधित डेटा पंजीकृत उपयोगकर्ताओं हेतु डाउनलोड के लिए एनजीडीआर पोर्टल पर उपलब्ध हैं।

एनएमईटी ने गवेषण लाइसेंस धारकों के लिए गवेषण व्यय आंशिक प्रतिपूर्ति योजना शुरू की है जहाँ एनएमईटी 20 करोड़ रुपये की सीमा के साथ प्रत्यक्ष लागत के 50% तक गवेषण

लाइसेंस धारकों द्वारा किए गए गवेषण व्ययों की आंशिक प्रतिपूर्ति करेगा। एनएमईटी 8 करोड़ रुपये की सीमा के साथ गवेषण के लिए किए गए 50% प्रत्यक्ष लागत तक गवेषण व्ययों की आंशिक प्रतिपूर्ति की योजना से संयुक्त लाइसेंस धारकों को सहायता भी करता है।

इसके अतिरिक्त, यदि ब्लॉक को जी4 से जी3 चरण में अद्यतित किया जाता है तो एनएमईटी सोना, आधारधातु, अन्य बहुमूल्य खनिजों, सामरिक/महत्वपूर्ण खनिजों और उर्वरक खनिजों के लिए ग्रीनफील्ड क्षेत्रों में जी4 मदों के लिए परियोजना की स्वीकृत लागत का 25% गवेषण प्रोत्साहन भी प्रदान करता है ।

(ख) : अगस्त 2015 में अपनी स्थापना के बाद से, एनएमईटी ने 2721.97 करोड़ रूपये की स्वीकृत लागत से बेसलाइन सर्वेक्षण के साथ-साथ क्षेत्रीय और विस्तृत गवेषण परियोजनाएं, केंद्रीय एजेंसियों और राज्य सरकारों को वित्तीय सहायता, राज्यों को प्रोत्साहन तथा एनईए और एनपीईए द्वारा खनिज गवेषण आदि सहित 471 परियोजनाओं को वित्त पोषित किया है। एनएमईटी विज्ञान और प्रौद्योगिकी (एसएंडटी) प्रिज्म कार्यक्रम के तहत परियोजनाओं को वित्त पोषित कर स्टार्ट-अप्स, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) में अनुसंधान और नवाचार और अलग-अलग नवप्रवर्तकों को प्रोत्साहित कर रहा है। आज तक, एनएमईटी ने 12.46 करोड़ रूपये की स्वीकृत लागत से 11 परियोजनाओं को वित्त पोषित किया है।

*****